

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,  
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,  
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 13 फरवरी, 2017

**विषय-** जिला नैनीताल की तहसील हल्द्वानी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) के न्यायालय हेतु सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना।

महोदय,

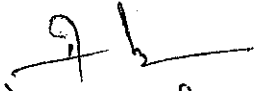
कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश के पत्र सं0-84/XXXVI(1)/139 एक/2002 दिनांक 10.02.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-38 एक(1)/न्याय विभाग/03 दिनांक 22.07.2003 के द्वारा जिला नैनीताल की तहसील हल्द्वानी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) के न्यायालय हेतु **सृजित 09 अस्थायी संवर्गीय पदों** की निरन्तरता वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये **दिनांक 01.03.2017 से दिनांक 28.02.2018 तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।**

2- उक्त कार्यालय में पद धारण करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तों सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय सुसंगत वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान सं0-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन न्यायालय-06-रेलवे मजिस्ट्रेट का न्यायालय-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-ए-1270/76-दस दिनांक 20.07.1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप सं0-ए-2-877/दस-92-24(8)/92 दिनांक 07.11.1992 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे हैं।

भवदीय

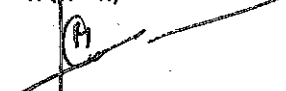
  
(आलोक कुमार वर्मा)  
सचिव

**संख्या- 52 /XXXVI(1)/ 2017-139 एक / 2002 तददिनांकित।**

**प्रतिलिपि-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. जिला न्यायाधीश/जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
3. वित्त अनुभाग-5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(महेश चन्द्र कौशिवा)  
अपर सचिव